THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) and (b) Yes. Sir. The request of the Government of Kerala is under examination.

Shortage of wheat, rice and sugar in PDS Shops

4162. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any shortage of wheat, rice and sugar in the States as reported by PDS shops;

(b) if so, the details thereof, Statewise;

(c) the total quantity of wheat, rice and sugar supplied to different States for distribution through PDS since July 1997; and

(d) the total shortage felt^ssessed and the steps Government propose to ensure timely availability of wheat, rice and sugar to the fair price shops in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The allocation of wheat, rice and sugar to StatevUTs for distribution through the Public Distribution System (PDS) from July, 1997 to July, 1998 is shown in the Statement *(See* below).

(d) As a step to ensure timely availability of wheat, rice and sugar under PDS, monthly allocation of these commodities to the States'UTs is made by the Government of India more than a month in advance. The responsibility for distribution to consumers through the Fair Price Shops rests with the State»UTs.

Statement

Total Quantity of Wheat Rice and Sugar Supplied to Different Stales for Distribution Through PDS From July 1997 to My 1998

(In 000 Tonnes)

States/UTs	Wheat	Rice	Sugar
Andhra Pradesh	167.00	2482.10	377.13
Arunachal Pradesh	7.74	41.86	5.01
Assam	363.90	657.45	125.43
Bihar	824.46	549.64	485.21
Goa	35.53	83.29	6.77
Gujarat	716.00	342.00	233.53
Haryana	194.65	0.00	93.12
Himachal Pradesh	144.26	154.00	28.32
Jammu & Kashmir	339^70	442.05	48.71
Karnataka	265.00	1020.00	254.16
Kerala	429.92	1979.60	164.52
Madhya Pradesh	590.87	446.55	374.13
Maharashtra	1343.84	706.22	445.38
Manipur	30.15	116.50	10.87
Meghalaya	29.24	220.34	10.22
Mizoram	20.73	124.46	4.06
Nagaland	40.71	129.18	7.70
Orissa	299.00	658.52	178.94

States/UTs	Wheat	Rice	Sugar
Punjab	66.69	12.48	114.90
Rajasthan	863.69	65.51	-249.52
Sikkim	7.62	93.03	2.41
Tamilnadu	320.00	1261.40	315.54
Tripura	20.80	19L95	16.02
Uttar Pradesh	1265.73	569.69	786.49
West Bengal	1259.30	535.85	385.99
A & N Islands	1.50	7.70	3.81
Chandigarh	20.05	3.33	5.25
D&N Haveli	2.40	5.85	0.73
Daman & Diu	1.85	5.45	0.45
Delhi	692.67	172.97	159.36
Lakshdweep	0.50	7.70	1.00
Pondicherry	6.30	23.20	5.87
TOTAL	10371.80	13109.87	4900.55

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश से गेहूं का निर्यात किया जाना

4163. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवेः** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य व्यापार निगम के सहोयग से वर्ष 1995-96-97 के दौरान मध्य प्रदेश से गेहूं का कोई निर्यात किया गया है,

(ख) यदि हां, तो उक्त दो वर्षों के दौरान राज्य से गेहूं की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया, और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य से गेहूं की कितनी मात्रा का निर्यात किये जाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव)ः (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग)भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1997-98 के दौरान गेहूं निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

4164. **चौधरी हरमोहन सिंह यादवः**

श्री नागमणि

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आय की तारीख में देश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की राज्य वार संख्या कितनी है,

(ख) क्या गोदामों की यह संख्या राज्य की मांग के अनुरुप पर्याप्त है,

(ग) क्या कुछ राज्यों में ये गोदाम जीर्ण शीर्ण स्थिति में है जिससे बहुमूल्य खाद्यात्र का भंडारण अत्यन्त कठिन हो गया है, औऱ

(घ) क्या सरकार ने इस संबध में कोई सर्वेक्षण कराया है?

खाद्य औऱ उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव)ः (क) 1.6.98 के स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गोदामों की संख्या संलग्र विवरण में दी गयी है, (नीचे देखिये)

जी, हां इसके अलावा , भारतीय खाद्य निगम को अपनी आवश्यकता पर निर्भर करते हुए सरकारी एजेन्सीयों और प्राइवेट पार्टियों से अतिर्कित गोदाम किराये पर लेने की आवश्यक शक्तियां प्राप्त हैं।